तिब्बती लोकतन्त्र स्थापना की ६०वीं वर्षगांठ के अवसर पर निर्वासित तिब्बती संसद का वक्तव्य*

आज तिब्बती पञ्चाङ्कानुसार वर्ष २१४७ १७ लोह (धातु)- मूषक वर्ष के ७वाँ मास (डोशिन दावा) कृष्ण पक्ष पञ्चदश के दिन तदानुसार वर्ष २०२०, ०२ सितम्बर है। यह एक महत्वपूर्ण दिन है, परम पावन जी के अद्‌भुत वैयक्तिक विशेषता, शक्ति व कृपा दृष्टि के कारण निर्वासित तिब्बती राजनीति में सम्यक लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था के रूप में स्थापित हुये साठ वर्ष पूर्ण हो गया है। और आज हम सभी इस वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर परम पावन १४वें दलाई लामा जी को समस्त तिब्बती जनताओं की ओर से साष्टाङ्ग प्रणाम करते हुये आभार व कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। निर्वासित तिब्बती संसद की ओर से मैं तिब्बत व तिब्बती जनता को सहयोग करने वाले दुनिया भर के सरकारें, संसद, सभी तिब्बत समर्थक संगठनों इत्यादि विश्व के शान्ति पसन्द समस्त जनताओं तथा तिब्बत के भीतर और निर्वासन, दोनों जगहों पर रहने वाले अपने प्यारे तिब्बती साथियों को मैं हार्दिक अभिनन्दन और शुभकामनायें देता हूँ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मानव जाति सम्बन्धी ऐतिहासिक घटनाओं में उत्पीड़न, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, जाति इत्यादि मानव समाज में श्रेष्ठ-तुच्छ भेदभाव वाली मानसिकता को समाप्त करता है। साथ ही इसमें सभी के प्रति समानता की विचारधारा के आधार पर समस्त जनता के हितों और चिन्ताओं को ध्यान में रखते हुये व्यवहार होता है। ऐसे व्यवस्था को आम जनता पसन्द करते हैं, वास्तव में इस तरह के महान आदर्श व्यवस्था को बनाने हेतु विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के ऐतिहासिक घटनाक्रमों में युद्ध, प्रत्याशी खड़ा करना, संघर्ष आदि का अन्ततोगत्वा उस परिणाम से ही विजय-पराजय का निर्धारित होता है। वास्तव में एक राष्ट्र का सफल होना अथवा लोकतन्त्र शासनशक्ति में बदलने की प्रयत्न करना जारी है। तिब्बती समाज के अन्दर लोकतन्त्र जो है, उसे तिब्बत के धार्मिक व राजनीति नेता परम पावन चौदहवें दलाई लामा जी के द्वारा जनताओं के संघर्ष, युद्ध इत्यादि के बिना किसी परिश्रम के तिब्बती जनता को उपहार स्वरूप भेंट में मिला है।

जब परम पावन ने तिब्बती समाज को बदलते समय की आवश्यकता को ध्यान में रखा, तब वह बहुत कम उम्र के थे। अतः तिब्बती के आध्यात्मिक नेता व अस्थायी प्रमुख के रूप में उत्तरदायित्व सम्भालने के तुरन्त बाद, उन्होंने सन् १९५२ को अलग से पहल के रूप में एक सुधार कार्यालय की स्थापना की। इसके अतिरिक्त सन् १९५४ में, उन्होंने तिब्बत की राजधानी ल्हासा में तिब्बत की नई न्यायिक व्यवस्था की एक शाखा स्थापित की, जहाँ नागरिक विवादों का निपटारा किया जाना था। ऐसी और कई अन्य पहल के साथ, आपने अद्भुत गम्भीर कृपालुता के साथ सराहनीय कर्मों को सुचरू रूप से सुधार व बेहतरी की। यह केवल परम पावन जी की अनुकम्पा व कृत्यों के आशीर्वाद से आपने तिब्बत के लोगों के लिये सदा सुखी और आनन्दमय समाज की स्थापना हेतु अत्यधिक प्रयास में लगे थे। इसी बीच साम्यवादी चीन शासन द्वारा तिब्बत पर अत्यधिक दमन को बढ़ाते गये, अन्ततः सन् १९५९ को सम्पूर्ण रूप से शान्तिप्रिय देश तिब्बत पर बलात् कब्ज़ा कर लिया गया। उसके पश्चात् परम पावन चौदहवीं दलाई लामा जी को पितृभूमि से पालयन होना पड़ा, भारत में शरण लेने को मज़बूर हुये।

निर्वासन में पधारने के पश्चात् शुरुआती वर्षों में जीवन-यापन के अनेकों कष्टभरी शरणार्थी स्थिति के होने पर भी परम पावन दलाई लामा जी ने आपने पूर्व योजना के अनुसार तिब्बत की राजनीति व्यवस्था को लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था में बनाने का तत्काल निर्देशित किया।

०३ फरवरी, १९६० को पवित्र तीर्थ स्थल बोधगया, बिहार में परम पावन जी को निर्वासित तिब्बत के तीनों प्रान्तों के जनता व सम्प्रदायों आदि के प्रतिनिधियों की ओर से दीर्घायु पूजा किया गया। साथ ही आपके उपदेशों को सुनने के बाद अनुशासन रूप से शपथपत्र प्रस्तुति के दौरान परम पावन जी ने कहा कि तिब्बत अब पहले के भाँति नहीं होगा, बल्कि तिब्बत को धार्मिक व राजनीति होने साथ साथ एक लोकतान्त्रिक सरकार का बनाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है, इस बारे में सूचना के रूप में मार्गनिर्देश किया गया। तदानुसार ०२ सितम्बर, १९६० को प्रथम निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने परम पावन जी के समक्ष शपथ लिया। इसके बाद तिब्बती लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था का श्रीगणेश हुआ।

१० अक्टूबर, १९६१ को, भविष्य तिब्बत के संविधान का संक्षित रुपरेखा पेश किया गया। उन तिब्बती जनता से प्राप्त सुझावों के आधार पर, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद में संशोधन व जोड़ना आदि जो भी उपयुक्त हो उसे करेंगे। उसके बाद धर्मशाला में जनता के साथ-साथ तिब्बती संसद के सांसदों द्वारा भी गहन विचार-विमर्श व चर्चा सहित संविधान को पारित किया। उस चर्चा के आधार पर, परम पावन ने संविधान की घोषणा की और यह स्पष्ट किया कि

यह तिब्बत के अपनी स्वतन्त्रता हासिल करने से पूर्व उदाहरण के तौर पर लागू किया जायेगा। भविष्य में तिब्बत को स्वतन्त्रता मिलते ही प्रथमतः इस संविधान को प्रयोग में लाया जायेगा। १० मार्च, १९६३ को तिब्बती राष्ट्र विद्रोह दिवस की चौथी वर्षगांठ के स्मरणोत्सव के दौरान अपने सन्देश में, भविष्य स्वतन्त्र तिब्बत के संविधान प्रारुप की घोषणा की। उस आधार पर परम पावन ने औपचारिक रूप से निर्वासन में तिब्बती प्रशासन के स्वरूप लोकतन्त्रीकरण में बदलने की घोषणा की, जिसमें निर्वासन में पहुँचे तिब्बती जनता के द्वारा समस्त तिब्बत के जनताओं का प्रतिनिधित्व के प्रतीकात्मक स्वरुप तीनों प्रान्तों के सांसदों का मतदान के द्वारा चुनाव करवाना है। ०२ सितम्बर, १९७५ से लेकर सरकार की ओर से तिब्बती लोकतान्त्रिक दिवस मानना प्रारम्भ करने के बाद से अब तक मानता चला आ रहा है।

वर्ष १९८० की शुरुआत से ही, परम पावन जी ने तिब्बती संसद और काशग के सदस्यों की संख्या को उचित रूप से बढ़ाने की एक के बाद एक दिशानिर्देश हुई। ताकि उन्हें अपनी भूमिका निभाने में और अधिक सफल बनाने की आवश्यकता को पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त, परम पावन ने इस सवाल पर तिब्बती जनता से सुझाव आमन्त्रित करने सहित कई कदमों में विचार माँगे, इस सवाल पर कि क्या काशग का नेतृत्व करने के लिये एक प्रधान मन्त्री को नियुक्त करने की आवश्यकता थी। बाद में सन् १९९० मई माह के अन्दर निर्वासन तिब्बतियों के लगभग ३६९ प्रतिनिधियों की एक विशेष आम सभा बुलाई गई, जिसमें अवस्थापरिवर्तनकालिक कलोन चुनाव, सांसद की संख्या बढ़ाने आदि का प्रस्ताव पारित किया गया। परम पावन जी ने निर्वासित तिब्बतियों के लिये एक लोकतान्त्रिक चार्टर का प्रारूप तैयार करने और साथ ही साथ भविष्य के तिब्बत के लिये मौजूद संविधान प्रारूप की समीक्षा के लिये एक संवैधानिक समीक्षा समिति के सीधे नियुक्त की। १९९१, १४ जून को ११वीं तिब्बती संसद के सत्र के दौरान निर्वासित तिब्बतियों चार्टर निर्धारित किया गया। उसी वर्ष २८ जून को परम पावन जी के द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद से निर्वासित तिब्बती प्रशासन एक प्रकार से बुनियादी दस्तवेज़ वाले आधुनिक लोकतान्त्रिक में परिवरतित हो गया।

वर्ष २००१ में, परम पावन जी ने अपने सन्देश में निर्वासन में तिब्बती लोगों के चार्टर के संशोधन का आह्वान करते हुये, तिब्बत के राजनीतिक मामलों से अर्ध-सेवानिवृत्ति ले ली। और राजनीति नेतृत्व कलोन ठ्रिपा का तिब्बती जनताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव करना प्रारम्भ हुआ। यह तिब्बती प्रशासनिक व्यवस्था के लोकतन्त्रीकरण विकास में प्रगति की ओर एक बड़ी कदम थी।

निर्वासन में तिब्बती लोगों के चार्टर में, यह प्रावधान किया था कि परम पावन दलाई लामा जी के अवतारितों ने क्रमशः तिब्बती सरकार के प्रशासनिक नेता और तिब्बत राज्य के प्रमुख होंगे। फिर भी, लोकतान्त्रिककरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिये, परम पावन ने २०११ में वर्तमान और भविष्य के दीर्घकालिक हितों और तिब्बती लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुये, जो कि उनकी महान् गदेन फ़ोडरंग प्राधिकरण ने पिछले लगभग ४०० वर्षों के सभी सरकारी और राजनीतिक अधिकारों को स्थानान्तरित करने का अत्यधिक महत्व वाला निर्णय लिया, जिसमें तिब्बती जनताओ द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने गये नेतृत्वों को हस्तान्तरित किया गया। आपने यह सुनिश्चित किया कि वास्तव में निर्वासित तिब्बती प्रशासन में न्यायिक अधिकार वाले आधुनिक लोकतान्त्रिक राजव्यवस्था का नींव को स्थिर करने का कार्य किया गया।

तिब्बती लोकतांत्रिक विकास यात्रा में तिब्बती चार्टर तथा चुनावी प्रावधान सहित अबतक २७ महत्वपूर्ण संशोधन किये जा चूके हैं। इसी तरह निर्वासित तिब्बती संसद का शीर्षक, सांसदों की संख्या व समय सीमा में भी क्रमशः परिवर्तन हुआ है। निर्वासित तिब्बती संसद के नाम पट्ट पर पहले Commission of Tibetan People's Deputies प्रयोग किया जाता था जिसे ७वें तिब्बती संसद द्वारा १८.१.१९८० को बदल कर Assembly of Tibetan People's Deputies किया गया। उसके पश्चात चौदहवें तिब्बती संसद के कार्यकाल में फिर से संशोधन कर Tibetan Parliament in Exile निर्वासित तिब्बती संसद रखा गया जो अभी तक कायम है। तिब्बती संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का नाम जो पहले Chairman and Vice Chairman था उसे Speaker and Deputy Speaker में संशोधित किया गया। पहले सांसदों की कुल संख्या १३ था, उसमें समय अनुकूल संख्या में परिवर्तन होता रहा। आज के स्थिति में तिब्बत के तीनो प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में दस-दस सांसद, बोन एवं बौद्ध मठ के चार सम्प्रदायों के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो सांसद, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका से दो सांसद,अमेरिका से दो सांसद। भारत,नेपाल और भुटान छोड़ बाकी एशिया ऑस्ट्रेलिया से दो सांसद, कुल सांसदो की संख्या ४५ है। ७वें संसद तक सांसदों की सदस्य के कार्यकाल तीन साल का हुआ करता था, ८वें संसद में कार्याकाल को बढ़ाकर पाँच वर्ष की गई जो अभी यथावत है। कुल मिलाकर, पिछले छः दशकों में समय और परिस्थिति के अनुरूप तिब्बती लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव कर शीर्ष नेता सिक्योंङ और सांसदों को सीधे जनता के मत द्वारा चुने जाते हैं। अपने नेता के जरिए लोकहित कार्यों की योजना बनाने एवं कार्यान्वयन हेतु बजट सत्र एवं समीक्षा सत्र निर्धारित की गई है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के अलावा स्थानीय न्याय आयोग, स्थानीय तिब्बती असेंबली, तिब्बती सेटेल्मेन्ट कार्यालय, दूतावास, तिब्बती फ्रीडम

मूवमेंट आदि संस्थाओं को सुदृढ़ किया है। आज के समय भारत, नेपाल व भुटान में ३८ तथा विदेश में १ कुल ३९ स्थानीय तिब्बती असेंबली, ५० तिब्बती सेटेल्मेंट कार्यालय, १३ दूतावास, ७५ तिब्बती फ्रीडम मूवमेंट आदि के माध्यम से लोकतंत्र का मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। तिब्बती प्रशासन के माध्यम मार्ग की नीति भी निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा पारित किया गया है। निर्वासन की ऐसी परिस्थिति में तिब्बती नागरिकों के समस्याओं का निपटारा, प्रशासन की नीतिगत फैसले लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है, जिसे दुनिया के कई देशों से साधुवाद एवं सराहना मिली है।

अभी हाल ही में, २८ व २९ अगस्त को, चीन के पीपुल्स रिपब्लिक के केन्द्रीय अधिकारियों के तिब्बत के कार्य पर तथाकथित ०७वें केन्द्रीय संगोष्ठी बीजिङ्ग में आयोजित की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार जिन लोगों ने उस संगोष्ठी में भाग लिया। जिसमें शी जिनपिंग आदि चीन के शीर्ष नेताओं, तिब्बत जैसे तथाकथित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जिसे चीन ने ऐतिहासिक तिब्बत को खण्डित किया था उन विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ नेता लोग भी शामिल थे। इस संगोष्ठी का अध्यक्षता शी जिनपिंग ने किया, उस समय, शी जिनपिंग ने कहा है कि “राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, शान्ति और स्थिरता को बनाये रखने के लिये पार्टी के संगठन और अधिकार को मजबूत किया जाना चाहिये, लोगों के जीवन स्तर में निरन्तरता, वृद्धि के साथ साथ संरक्षण करने, पर्यावरण की स्थिति में सुधार और प्रयासों की सुरक्षा की तरीके को मजबूत किया जाना चाहिये; सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और सीमान्त सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये, एक नये आधुनिक समाजवादी तिब्बत के निर्माण के लिये अत्यधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है जो एकजुट, समृद्ध, सद्भाव, सांस्कृतिक रूप से उन्नत, सामंजस्यपूर्ण और सन्दुर हो।” के बारे में हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि “चीनी के सन्दर्भ में निश्चित रूप से अपने कानूनों के तहत धार्मिक कार्य करने वालों के प्रति सख्ती अपनाये रखना है।” और यह भी कहा कि “तिब्बत से सम्बन्धित कार्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा और जातीय एकजुटता को मजबूत करने पर आधारित होना चाहिये। तिब्बत के जनताओं को अलगाववादी के प्रति विरोध के गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाने के लिये जनताओं को चीनी शिक्षा व मार्गदर्शन करने में और अधिक प्रयास करना चाहिये। जिसके चलते तिब्बत में स्थिरता के लिये अभेद्य किले के रूप में निर्माण में योगदान हो सके। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास पर सही मार्गदर्शन देने के लिये शिक्षा पर जोर देना चाहिये, नये चीन का इतिहास, चीन के सुधार का इतिहास को खोलने और समाजवादी व्यवस्था का विकास। और शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थानीय तिब्बत क्षेत्र और चीनी मातृभूमि के बीच सम्बन्धों पर गरहाई से ध्यान केन्द्रित करके, विभिन्न जातीय समूह के लोगों को राष्ट्र के बारे में उत्कृष्ट दृष्टिकोण

विकसित करने के लिये इतिहास के बार में, जातीय राष्ट्रीयताओं के बारे में, संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में निर्देशित किया जाना चाहिये।" और इस प्रकार इस संगोष्ठी से जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि चीन की सरकार का तिब्बत में अपनी कट्टरपंथी दमनकारी नीति में कोई भी बदलाव लाने का कोई इरादा नहीं था। और इस संगोष्ठी में यह स्पष्ट कर दिया कि चीन की योजना तिब्बत के इतिहास की विकृति, अपनी संस्कृति के पुनर्संयोजन और अपनी धार्मिक परम्पराओं की मिलावट पर निर्देशित अपने प्रचार प्रयासों को आगे बढ़ाने की थी। इस तरह की बैठकें दिखावा के अलावा और कुछ नहीं हैं बाहरी दुनिया को गुमराह करते हैं जबकि उनका मुख्य वास्तविक उद्देश्य तिब्बत देश को चीन के प्रान्तों में बदलने का उपकरण के रूप में प्रयोग करने की है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही मायने में लागु करने के लिए अपनी जीत दुसरों की हार के सोच को त्यागना होगा। विशेषकर सन् २०२१ के सिक्योङ तथा संसद सदस्यों के चुनाव में निर्वासित तिब्बती चार्टर में उल्लेखित तिब्बत वासियों के कर्तव्यों एवं अधिकारों का सही मायने में पालन हो। जिससे संप्रदाय और प्रांतो के बीच में मुठभेड़ व मतभेद न हो। विशेषकर परम पावन दलाई लामा जी का मन न व्यथित हो तथा तिब्बत में रह रहे हमारे अपनों के साहस पर असर न पड़े। परम पावन चौदहवें दलाई लामा जी के कुशल नेतृत्व की छत्रछाया में बोन व चारों सम्प्रदाय तथा तीनों प्रांतों के लोगों का दुख या सुख सभी परिस्थिति में समान भाव रखने की हमारी एकता जिस पर हम गर्व करते हैं, उस एकता को खंडित करने में कुछ लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का विरोध करना अनिवार्य है। हमारे कुछ नसमझ लोग ऐसे लोगों के बहकावे में आ सकते हैं, ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है की ऐसे कृत्यों से बचा जाए।

चीन के शहर वुहान से फैले कोविड-१९ महामारी की स्थिति उत्पन्न होकर अभी आठ महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक इससे बचाव का कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। अन्य संक्रमण रोगों से अलग इस अनिश्चित महामारी के कारण ज्यादातर देशों को असहनीय हानि पहुँची है, निर्वासित तिब्बती संसद अत्यन्त खेद एवं सहानुभूति प्रकट करते हैं। भारत में शुरुआती संक्रमण से अब दिनों दिन इस महामारी से संक्रमित संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तालाबंदी खोलने की चौथी दिशा निर्देश के साथ ही संक्रमण गति में तेजी के कारण हर प्रकार से परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। इसलिए सब को इस संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करना चाहिये। इस बार १६वें संसद के १०वें सत्र को स्थागित करना पड़ा है, और साथ ही भारत तथा विदेश के तिब्बती सांसदों का दौरा भी रद्द करना पड़ा है।

तिब्बती निवासरत प्रदेशों के विधान सभाओं में तिब्बत समर्थक समूह का गठन तथा केन्द्र में सर्वदलिय तिब्बत समर्थक का पूर्णगठित करने में इस महामारी के कारण बाधा पहुँची है।

परम पावन दलाई लामा जी के द्वारा किए गए अथक प्रयास से ही हमें लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम सब उनके आभारी रहेंगे। पिछले साठ सालों में निर्वासन की परिस्थिति, राजनीतिक, धर्म, संस्कृति एवं भाषा संरक्षण, तिब्बत मुक्ति साधना आदि में हमेशा मार्गदर्शन एवं सहायता देने वाले दुनिया के सभी देशों के सरकार व जनता तथा खासकर भारत सरकार और जनता को बहुत आभार एवं धन्यवाद अर्पित करते हैं।

अन्त में, परम पावन दलाई लामा जी दीर्घायु हो, उनके हर मनोकामना पूर्ण हो और तिब्बत समस्या का समाधान यथाशीघ्र हो ऐसी कामना करते हैं।

निर्वासित तिब्बती संसद
०२ सितम्बर, २०२०

Tibetan Parliamentary Secretariat

---

* इस हिन्दी अनुवाद में किसी भी प्रकार के विसंगति के मामले में, सभी प्रयोजन हेतु तिब्बती मूल को आधिकारिक और अन्तिम माना जाना चाहिये।